



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102023-249107
CG-DL-E-03102023-249107

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 242]
No. 242]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 29, 2023/आश्विन 7, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 29, 2023/ASVINA 7, 1945

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2023

मामला संख्या: एडी (ओआई) - 09/2023

विषय: चीन जन.गण. में मूलतः अथवा वहां से निर्यातित "आइसोप्रोपिल एल्कोहॉल" के आयात के संबंध में पाटन रोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 6/09/2023-डीजीटीआर.—1. मेसर्स दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जिसे बाद में "आवेदक" के रूप में संदर्भित किया गया है) ने 1995 और उसके बाद यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिस आगे 'अधिनियम' भी कहा गया है) समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "एडी नियमावली" भी कहा गया है) के नियमों के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके बाद 'प्राधिकरण' के रूप में संदर्भित) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन.गण. (इसके बाद "विषय देश" के रूप में संदर्भित) से उत्पन्न या निर्यात किए गए "आइसोप्रोपिल अल्कोहल" (इसके बाद 'विचाराधीन उत्पाद' या 'विषय वस्तुओं' या 'आईपीए' के रूप में संदर्भित) के आयात पर पाटन रोधी जांच शुरू करने की मांग करता है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबंधित देश से उत्पन्न या निर्यात किए गए कथित पाटित आयात के कारण घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति हो रही है और संबंधित देश से विषय वस्तुओं के आयात पर पाटन रोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. विचाराधीन उत्पाद आइसोप्रोपिल अल्कोहल है।
4. आईपीए रासायनिक सूत्र $CH_3CHOHCH_3$ के साथ एक यौगिक है। यह एक मजबूत गंध के साथ एक रंगहीन, ज्वलनशील तरल है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के औद्योगिक और घरेलू रसायनों के निर्माण के लिए किया जाता है और थोक दवाओं और दवा योगों के उत्पादन में प्रमुख अनुप्रयोगों को पाता है जो दवा निर्माण में महत्वपूर्ण हैं। इसका उपयोग एंटीसेप्टिक्स, कीटाणुनाशक और डिटर्जेंट जैसे रसायनों में सामान्य घटक के रूप में भी किया जाता है। उत्पाद को परिभाषित करने वाले आवश्यक पैरामीटर इसकी प्रतिशत शुद्धता, विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण, अवशिष्ट अशुद्धियां, पानी की मात्रा और अपवर्तक सूचकांक हैं।
5. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ वर्गीकरण के एचएस कोड 2905 12 20 के तहत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और प्रस्तावित जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
6. वर्तमान जांच के पक्षकार पीयूसी पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं और इस जांच शुरूआत अधिसूचना के पैराग्राफ 24 में दर्शाए गए अनुसार प्राधिकरण के समक्ष दायर दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण के प्रसार के 15 दिनों के भीतर पीसीएन, यदि कोई हो, का प्रस्ताव कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

7. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित विषय वस्तु में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है और दोनों समान वस्तुएं हैं। आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद आवश्यक उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन और माल के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। उपरोक्त दोनों का परस्पर उपयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। दोनों तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं, और इसलिए नियमों के तहत इन्हें 'समान वस्तु' के रूप में माना जाना चाहिए। इस प्रकार वर्तमान जांच की शुरूआत के प्रयोजनों के लिए आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु को प्रथम दृष्टया चीन जन. गण. से आयात किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।

ग. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

8. आवेदन मेसर्स दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक के अलावा भारत में एक अन्य उत्पादक है अर्थात् मेसर्स दीपक फेनोलिक्स लिमिटेड जिसने आवेदक द्वारा दायर तत्काल आवेदन का समर्थन किया है। आवेदक और मेसर्स दीपक फेनोलिक्स लिमिटेड भारत में विचाराधीन उत्पाद के केवल दो उत्पादक हैं। उनका उत्पादन भारत में कुल घरेलू उत्पादन का 100% है।
9. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण नोट करता है कि आवेदक एडी नियमों के नियम 2 (बी) के अर्थ के भीतर 'घरेलू उद्योग' का गठन करता है और आवेदन एडी नियमों के नियम 5 (3) के संदर्भ में स्थायित्व के मानदंडों को पूरा करता है।

घ. संबद्ध देश

10. वर्तमान जांच में विषय देश चीन जन. गण. है।

ड जांच की अवधि

11. जबकि आवेदक ने जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक जांच की अवधि (पीओआई) प्रस्तावित की है, प्राधिकरण ने जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल 2022 से मार्च 2023 (12 महीने) तक अपनाई है। क्षति की जांच 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 और पीओआई के लिए प्रस्तावित है।

च. प्रक्रिया

12. इस जांच में एडी नियमों के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

छ. कथित पाटन के लिए आधार**चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य**

13. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और चीन जन. गण. के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए कि विषय वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रबल है। जब तक चीन जन. गण. के उत्पादक यह नहीं दिखाते हैं कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रबल है तब तक उनके सामान्य मूल्य को पाटनरोधी नियम, 1995 के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

14. इसलिए जांच शुरू करने के उद्देश्य से आवेदक की उत्पादन लागत के अनुमानों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण किया गया है, जो उचित लाभ मार्जिन के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों के साथ विधिवत समायोजित है।

निर्यात कीमत

15. डीजीसीआईएस द्वारा उपलब्ध कराए गए लेनदेन-वार आयात आंकड़ों पर विचार करके संबंधित देश से विषय वस्तुओं के निर्यात मूल्य का अनुमान लगाया गया है। शुद्ध निर्यात मूल्य पर पहुंचने के लिए बंदरगाह व्यय, अंतर्देशीय माल ढुलाई, समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, बैंक कमीशन ऋण लागत के कारण मूल्य समायोजन किए गए हैं।

पाटन मार्जिन

16. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना एक्स-फैक्ट्री स्तर पर की गई है जो प्रथम दृष्टया स्थापित करता है कि चीन जन. गण. से आयातित विषय वस्तुओं के संबंध में पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से ऊपर है। इस प्रकार इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद को चीन जन. गण. के निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में पाटित किया जा रहा है।

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध

17. आवेदक ने पाटित किए गए आयात के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रदान किया है। संबद्ध देश से संबद्ध आयात की मात्रा पूर्ण और सापेक्ष दृष्टि से महत्वपूर्ण है। समग्र रूप से संबद्ध देश से कीमत में कटौती सकारात्मक और महत्वपूर्ण है। घरेलू उद्योग का उत्पादन घटा है और घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। पाटित किए गए आयात के कारण कीमत में गिरावट और अवसाद घरेलू उद्योग को पूरी लागत वसूलने और रिटर्न की उचित दर हासिल करने के लिए अपनी कीमतें बढ़ाने से रोक रहा है। घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी उस मांग से कम है जिसे वह पूरा कर सकता है। संबद्ध आयातों का घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिसके कारण नकद लाभ, पीबीआईटी और आरओसीई में बहुत महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है। घरेलू उद्योग की वस्तुसूची स्तर में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

झ. पाटन रोधी जांच की शुरुआत

18. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर और आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संबंधित देश में उत्पन्न या निर्यात किए गए उत्पाद के पाटन के संबंध में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर विषय वस्तुओं की कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को परिणामी नुकसान और इस तरह की क्षति और पाटित किए गए आयात के बीच कारण संबंध, और अधिनियम की धारा 9ए के अनुसार जिसे एडी नियमों के नियम 5 के साथ पढ़ा जाता है प्राधिकरण इसके द्वारा संबंधित देश में उत्पन्न या निर्यात किए जाने वाले विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन के अस्तित्व, डिग्री और प्रभाव को निर्धारित करने और पाटन रोधी शुल्क की उचित मात्रा की सिफारिश करने के लिए एक पाटन रोधी जांच शुरू करता है। जो यदि लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

19. निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने वाले सभी पत्र ई-मेल पत्तों dd11-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in पर तथा उनकी एक प्रति adg14-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in को भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
20. संबंधित देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबंधित देश की सरकार और भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं, जो विषय वस्तुओं से जुड़े होने के लिए जाने जाते हैं, को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी प्रासंगिक जानकारी दर्ज कर सकें। ऐसी सभी जानकारी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित फॉर्म और तरीके से दायर की जानी चाहिए।
21. कोई अन्य इच्छुक पक्षकार भी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिसों द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से इस दीक्षा अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संबंधित एक प्रस्तुति दे सकता है।
22. प्राधिकरण के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुति देने वाले किसी भी पक्ष को अन्य इच्छुक पक्षों को इसका एक गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराना आवश्यक है।
23. इच्छुक पार्टियों को आगे निर्देशित किया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in/>) को नियमित रूप से देखते रहें और जानकारी के साथ-साथ आगे की जांच पड़ताल प्रक्रियाओं से अवगत रहें।

ट. समय सीमा

24. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पतों dd11-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in तथा adg14-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in को एक प्रति के साथ प्राधिकारी द्वारा आवेदक के आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण को परिचालित किए जाने अथवा एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी एडी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
25. सभी इच्छुक पार्टियों को सलाह दी जाती है कि वे तत्काल मामले में अपनी रुचि (हित की प्रकृति सहित) बताएं और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के जवाब दाखिल करें।
26. जहां कोई इच्छुक पक्ष प्रस्तुतियाँ दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है, उसे एडी नियम, 1995 के नियम 6(4) के संदर्भ में ऐसे विस्तार के लिए पर्याप्त कारण प्रदर्शित करना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आना चाहिए।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

27. जहां वर्तमान में कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है या प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर सूचना देता है, वहां उसे एडी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी की गई संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
28. ऐसे अनुरोध पर प्रत्येक पृष्ठ पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी को किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा और प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने की स्वतंत्रता होगी।
29. गोपनीय संस्करण में वे सभी जानकारी शामिल होंगी, जो प्रकृति से, गोपनीय और / या अन्य जानकारी है, जिसे ऐसी जानकारी का आपूर्तिकर्ता गोपनीय के रूप में दावा करता है। ऐसी जानकारी के लिए जिसे प्रकृति से गोपनीय होने का दावा किया जाता है, या जिस जानकारी पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, सूचना के आपूर्तिकर्ता को प्रदान की गई जानकारी के साथ एक अच्छा कारण विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी का खुलासा क्यों नहीं किया जा सकता है।
30. इच्छुक पक्षों द्वारा दायर की गई जानकारी का गैर-गोपनीय संस्करण गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय जानकारी अधिमानतः अनुक्रमित या रिक्त की गई हो (जहां अनुक्रमण संभव नहीं है) और ऐसी जानकारी को उस जानकारी के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से संक्षेप में किया जाना चाहिए जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है।
31. गैर-गोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तार में होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत जानकारी के सार की उचित समझ हो सके। हालांकि असाधारण परिस्थितियों में गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाला पक्ष यह संकेत दे सकता है कि ऐसी जानकारी सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है और नियम 1995 के नियम 7 के संदर्भ में पर्याप्त और पर्याप्त स्पष्टीकरण वाले कारणों का एक बयान, और प्राधिकरण द्वारा जारी उचित व्यापार नोटिस, कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है, प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।
32. इच्छुक पक्ष इस जांच शुरूआत अधिसूचना के पैराग्राफ 24 में दर्शाए गए दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण के प्रसार की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।
33. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना किया गया कोई अनुरोध या एडी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार गोपनीय दावे संबंधी किसी अनुरोध को पर्याप्त और पूरे कारणों के विवरण के बिना प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
34. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक है या यदि जानकारी का आपूर्तिकर्ता या तो जानकारी को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी जानकारी की अवहेलना कर सकता है।
35. प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता की आवश्यकता को संतुष्ट होने और स्वीकार करने पर प्राधिकारी ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्ष के विशिष्ट प्राधिकरण के बिना किसी भी पक्ष को इसका खुलासा नहीं करेगा।
36. पंजीकृत इच्छुक दलों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी जिसमें उन सभी को अनुरोध किया जाएगा कि वे अपनी प्रस्तुतियों के गैर-गोपनीय संस्करण और अन्य जानकारी को अन्य सभी इच्छुक पक्षों को ईमेल करें।

ड. असहयोग

37. यदि कोई इच्छुक पक्ष इस प्रारंभिक अधिसूचना में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय के भीतर या उचित अवधि के भीतर या अन्यथा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, या बाद में अलग-अलग संचार के माध्यम से प्रदान की गई समय अवधि में आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है तो प्राधिकरण ऐसे इच्छुक पक्ष को गैर-सहयोगी घोषित कर सकता है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड कर सकता है और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है। जैसा कि यह उचित लगता है।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**Department of Commerce**

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2023

Case No. AD(OI) –09/2023

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of “Isopropyl alcohol” (IPA) originating in or exported from China PR.

F. No. 6/09/2023-DGTR.—M/s Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Limited (hereinafter referred to as the “applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the ‘Authority’), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Rules’), seeking initiation of an anti-dumping investigation on imports of “isopropyl alcohol” (hereinafter referred to as the ‘product under consideration’ or ‘subject goods’ or ‘IPA’), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the “subject country”).

2. The applicant has alleged that material injury is being caused to the domestic industry due to the alleged dumped imports, originating in or exported from the subject country and has requested for the imposition of anti-dumping duties on the imports of the subject goods from the subject country.

A. Product under Consideration

3. The product under consideration is isopropyl alcohol.

4. IPA is a compound with the chemical formula $\text{CH}_3\text{CHOHCH}_3$. It is a colorless, flammable liquid with a strong odor. It is used to manufacture a wide variety of industrial and household chemicals, and finds major applications in the production of bulk drugs and drug formulations which are vital in the pharmaceutical manufacturing. It is also used as common ingredient in chemicals such as antiseptics, disinfectants, and detergents. The essential parameters that define the product are its percentage purity, specific gravity, residual impurities, water content, and refractive index.

5. The product under consideration is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under the HS Code 2905 12 20 of the Customs Tariff Classification. The customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration for the proposed investigation.

6. The parties to the present investigation may provide their comments on the PUC and propose PCNs, if any, within 15 days of circulation of the non-confidential version of the documents filed before the Authority as indicated in paragraph 24 of this initiation notification.

B. Like Article

7. The applicant has submitted that there are no significant differences in the subject goods produced by the applicant and exported from the subject country and both are like articles. The product produced by the applicant and imported from the subject country are comparable in terms of essential product characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & usage, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and have been using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable, and hence, should be treated as ‘like article’

under the Rules. Thus, for the purposes of initiation of the present investigation, the article produced by the applicant has been *prima facie* considered as like article to the product being imported from China PR.

C. Domestic Industry & Standing

8. The application has been filed M/s Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Limited. Apart from the applicant, there is one other producer in India, viz. M/s Deepak Phenolics Limited, which has supported the instant application filed by the applicant. The applicant and M/s Deepak Phenolics Limited are the only two producers of the product under consideration in India. Their production together constitutes 100% of the total domestic production in India.

9. In view of the above, the Authority notes that the applicant constitutes 'domestic industry' within the meaning of Rule 2(b) of the AD Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the AD Rules.

D. Subject Country

10. The subject country in the present investigation is China PR.

E. Period of Investigation

11. While the applicant has proposed the period of investigation (POI) from January 2022 to December 2022, the Authority has adopted the POI from April 2022 to March 2023 (12 months) for the subject investigation. The injury period proposed to be examined is 1st April 2019 to 31st March 2020, 1st April 2020 to 31st March 2021, 1st April 2021 to 31st March 2022 and the POI.

F. Procedure

12. The provisions stipulated in of Rule 6 of the Anti-Dumping Rules shall be followed in this investigation.

G. Basis for alleged dumping

Normal Value for China PR

13. The applicant has submitted that China PR should be treated as a non-market economy, and that producers from China PR should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to the production and sales of the subject goods. Unless the producers from China PR show that such market economy conditions prevail, their normal value should be determined in accordance with Para 7 of Annexure-I to the Anti-Dumping Rules, 1995.

14. Therefore, for the purpose of initiation of the investigation, the normal value has been constructed based on the estimates of cost of production of the applicant duly adjusted with selling, general and administrative expenses, along with a reasonable profit margin.

Export Price

15. The Export price of the subject goods from the subject country has been estimated by considering transaction-wise import data provided by DGCI&S. Price adjustments have been made on account of port expenses, inland freight, ocean freight, marine insurance, bank commission & credit cost to arrive at the net export price.

Dumping Margin

16. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* establishes that the dumping margin is above the *de minimis* level with respect to the subject goods imported from China PR. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration from China PR is being dumped in the domestic market of India by the exporters from China PR.

H. Injury and Causal Link

17. The applicant has provided *prima facie* evidence with respect to the injury suffered by the domestic industry because of the dumped imports. The volume of the subject imports from the subject country is significant in absolute as well as relative terms. The price undercutting from the subject country as a whole is positive and significant. The production of the domestic industry has declined. The capacity utilisation of the domestic industry has declined. The price suppression and depression caused by the dumped imports have been preventing the domestic industry from increasing its prices to recover the full cost and achieve reasonable rate of returns. The market share of the domestic industry is below the demand which it can cater. The subject imports have had an adverse impact on the profitability parameters of the domestic industry due to which the cash profits, PBIT, and ROCE have registered a very significant decline. There has also been a significant increase in the inventory levels of the domestic industry.

I. Initiation of Anti-Dumping Investigation

18. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicant and having reached satisfaction based on the *prima facie* evidence submitted by the applicant concerning the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, the consequential injury to the domestic industry as a result of the alleged dumping of the subject goods and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from the subject country and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

J. Submission of Information

19. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses dd11-dgtr@gov.in and ddl6-dgtr@gov.in with a copy to adg14-dgtr@gov.in and adv13-dgtr@gov.in. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

20. The known producers/exporters in the subject country, the Government of the subject country through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.

21. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.

22. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

23. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (<https://www.dgtr.gov.in/>) to stay updated and apprised with the information as well as further processes related to the investigation.

K. Time Limit

24. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at email address dd11-dgtr@gov.in and ddl6-dgtr@gov.in with a copy to adg14-dgtr@gov.in and adv13-dgtr@gov.in within 30 days from the date on which the non-confidential version of the documents filed by the domestic industry would be circulated by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules.

25. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.

26. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

L. Submission of information on confidential basis

27. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.

28. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as “non-confidential” information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

29. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

30. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
31. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
32. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents as indicated in paragraph 24 of this initiation notification.
33. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
34. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
35. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.
36. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.

M. Non-Cooperation

37. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority